सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, मंगलवार, 24 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 173, पृष्ठः 8+4

इनसाइड बृजेश पाठक-सतीश महाना की मुलाकात के मायने!... » Pg 03

कोई मुद्दा है तो हम मिलने को तैयार : चुनाव आयोग

» Pg 12

शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक चार राज्यों के सीएम रहे मौजूद

बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मप्र के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव मौजूद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

वाराणसी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में अमित शाह और चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मप्र के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव मौजूद हैं।

गृहमंत्री अमित शाह काशी में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में भाजपा शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इससे पहले उत्तराखंड मेजबान था और वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। बैठक में वहां के सीएम की जगह राज्य के गृहमंत्री शामिल हुए थे।

शाह सोमवार की शाम काशी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोटर पर सीएम योगी ने स्वागत किया। यहां से वह सीधे कालभैरव के दर्शन के लिए गए। रास्ते में 13 जगहों पर भाजपा कार्यकताओं ने उनका हर हर महादेव के उद्घोष, शंखध्वनि के साथ स्वागत किया। सीएम योगी ने ताज होटल में सभी अतिथियों को रात्रि भोज दिया। इसमें शाह के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मप्र के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव मौजूद रहे।

सामाजिक विकास, पर्यावरण, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर बात : मंगलवार की सुबह 11 बजे से नदेसर स्थित ताज होटल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जो बिना केंद्र की सहायता के मुद्दे राज्य सुलझा नहीं सकते हैं।

इसमें राज्य की संपत्ति, पानी विवाद या सीमा विवाद से जुड़े मामले भी हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास, पयाज़्वरण, कानून व्यवस्था समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बात की जाएगी।

संघर्ष विराम के एलान का असर

एअर इंडिया ने फिर शुरू की पश्चिम एशिया यूरोप की उड़ानें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया गया था या उनका मार्ग बदल दिया गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से संघर्ष विराम के एलान के बाद हवाई सेवा फिर से बहाल होती नजर आ रही है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एअर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह इस क्षेत्र में अपनी उड़ानें धीरे-धीरे फिर से शुरू करेगी। पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र फिर से खुल रहे हैं, इसलिए उड़ानों का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। एअर इंडिया ने यह भी कहा कि आज से यूरोप के लिए और यूरोप से आने वाली उड़ानें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, जैसे-जैसे पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र धीरे-धीरे फिर से खुल रहे हैं, एयर इंडिया आज से इस क्षेत्र में अपनी उड़ानें धीरे-धीरे शुरू करेगी। पश्चिम एशिया के लिए और वहां से आने वाली उड़ानों का संचालन 25 जून से पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। यूरोप के लिए और यूरोप से आने वाली उड़ानें, जो पहले रद्द की गई थीं, उन्हें भी आज से धीरे-धीरे फिर से शुरू किया जा रहा है।

चर्चा में खबर

पूर्व विधायक सुरेश राठौर को महंगा पड़ा एक्ट्रेस का इश्क

भाजपा ने पूर्व विधायक को भेजा कारण बताओ नोटिस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उत्तराखंड। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सहारनपुर निवासी महिला उर्मिला सनावर को एक संयुक्त प्रेस वार्ता में अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।

इससे पहले दोनों के बीच गंभीर विवाद और मुकदमेबाजी का दौर चला था, जिसमें राठौड़ ने उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, वहीं उर्मिला ने उनके साथ शादी होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर कई निजी तस्वीरें साझा की थीं।

» महिला उर्मिला सनावर को एक संयुक्त प्रेस वार्ता में अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया

» इससे पहले दोनों के बीच विवाद था, जिसमें राठौड़ ने उर्मिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था

संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों ने कहा कि अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है और आपसी सहमति से वे इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं। उर्मिला ने भी प्रेस के सामने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि राठौड़ की गतिविधियों से संगठन की छवि धूमिल हुई है और उन्हें 7 दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अनुशासन समिति की ओर से यह कारग्वाई की गई है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार की यूसीसी कानून के अंतर्गत अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह विवाद पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के उर्मिला सनावर को दूसरी पत्नी स्वीकार करने के बाद उठा।

कागजी चिलम में सुलगता बचपन

गांजे की लत ने छीना बच्चों का भविष्य

- 12 से 18 साल के बच्चे गांजा और चरस के आदी, बेटियों तक पहुंचा नशा
- गंगा बैराज, स्कूलों और पार्कों में फैल रहा नशे का खुला नेटवर्क
- उड़ीसा-बुंदेलखंड से आ रहा गांजा, कानपुर का कंजड़पुरवा बना हब
- पुलिस की चुप्पी पर उठते सवाल, दिखावटी है चौकियों में 'तौल' की तैयारी

शिवांक अग्निहोत्री स्वराज

कानपुर। कभी उद्योग, शिक्षा और होनहार युवाओं के लिए पहचाना जाने वाला कानपुर अब नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। लगभग दो दशक पहले तक जहां शहर के युवा देश-विदेश में नाम रोशन करते थे, वहीं अब 12 से 18 वर्ष के किशोर एवं किशोरियां गांजे और चरस के आदी होते जा रहे हैं।

मिट्टी की पारंपरिक चिलम की जगह अब 'कागजी चिलम' ने ले ली है, जिसने नशे को बेहद आसान और सस्ता बना दिया है। खासकर गंगा बैराज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नाबालिग लड़के-लड़कियों को खुलेआम नशा करते देखा जाना अब आम बात हो गई है।

कागजी चिलम ने बढ़ाया काला कारोबार

सूत्रों की मानें तो गांजा उड़ीसा और बुंदेलखंड से कानपुर के कंजड़पुरवा तक पहुंचता है। यहीं से फुटकर कारोबारी इसे ग्राम व किलो के हिसाब से शहर भर में सप्लाई करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गांजा बेचने से पहले कथित तौर पर स्थानीय पुलिस चौकियों से 'सेटिंग' की जाती है। इतना ही नहीं, कई थानों में तो गांजा तौलने के लिए बाकायदा तराजू तक मौजूद हैं। परंतु जहां कुंटलों में नशे का कारोबार हो रहा है, वहां पुलिस की निगाह तक नहीं पहुंच रही। शहर के स्कूलों, पार्कों और पब्लिक स्पॉट्स के पास कई दुकानदार न सिर्फ चिलम, बल्कि गांजा भी बेचते पाए जाते हैं।

कब जागेगा प्रशासन? नाबालिगों को चाहिये संरक्षण, सिर्फ भाषण नहींअब समय आ गया है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को उतनी ही गंभीरता से ले, जितनी एंटी रोमियो स्क्वॉड या सड़कों पर हेलमेट जांच को दी जाती है। जिन बच्चों के कंधे पर देश का भविष्य टिका है, वे स्कूल बैग में किताबों के साथ कागजी चिलम लिए घूम रहे हैं। इस अवैध कारोबार की जड़ें गहरी हो रही हैं, और यदि इसे अभी नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में कानपुर नशे के नक्शे पर एक बदनाम शहर बन जाएगा। ज़रूरत है कि स्कूलों में स्वास्थ्य परीक्षण हो, पार्कों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाए और गांजा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

चार फीट गहरे स्वीमिंग पूल में ठेकेदार डूबा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के सनिगवां स्थित रिसॉर्ट के स्वीमिंग पूल में रविवार देर रात हादसा हुआ। इसमें चार फीट गहरे स्वीमिंग पूल में ठेकेदार की डूबकर मौत हो गई। इंस्पेक्टर चकेरी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

कानपुर में चकेरी स्थित एक रिसॉर्ट में रविवार रात दोस्तों संग पूल पार्टी कर रहा नगर निगम का एक ठेकेदार चार फीट गहरे स्वीमिंग पूल में डूब गया। पास में ही पानी में अठखेलियां कर रहे दोस्तों के पास जब उसका शव उतराता हुआ पहुंचा, तो घटना का पता चला। सभी उसे कांशीराम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वार्ड-ब्लॉक किदवईनगर निवासी शैलेंद्र सिंह की कलक्टरगंज में रुई की आढ़त है। उनका इकलौता बेटा शिखर सिंह (24) नगर निगम में ठेकेदारी करता था। रविवार शाम को वह इलाके में रहने वाले अंकित, विशाल, देवेंद्र, भोलू और शिवम व एक अन्य दोस्त के संग सनिगवां स्थित एक रिसॉर्ट में मौज मस्ती करने गया था।

शव उतराकर नहा रहे दूसरे युवकों के पास पहुंचा

दोस्तों के अनुसार देर रात सभी स्वीमिंग पूल में नहा रहे थे। रात 12:49 बजे तेज आवाज में गाना बज रहा था। इस दौरान मस्ती में सराबोर युवक पानी में झूम रहे थे।शिखर नहाते हुए पूल में दोस्तों से अलग हो गया और अचानक डूबने लगा। काफी देर तक पानी में अंदर रहने के बाद उसका शव उतराकर पास में नहा रहे दूसरे युवकों के पास पहुंच गया।

डूबते दोस्त पर नहीं पड़ी किसी की नजर

दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और आनन-फानन कांशीराम अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिसॉर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज के अनुसार नहाने के दौरान शिखर का संतुलन बिगड़ गया और वह खुद को संभाल नहीं पाया। फुटेज से पता चला है कि कुछ सेकेंड पानी के अंदर रहने के बाद शिखर ने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसका सिर पानी के अंदर और पैर ऊपर हो गए।उसने खुद को संभालने की भरसक कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शिखर सिंह का सिर डुबकी लगाने के 17 सेकेंड बाद बाहर आया। फिर एकाएक नीचे गया और 21 सेकेंड बाद दोनों पैर ऊपर आए और फिर नीचे चला गया।

बृजेश पाठक-सतीश महाना की मुलाकात के मायने!

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह व तत्कालीन सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी विवाद में महराजपुर से 9 बार के विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई विधायकों ने सीएमओ के लिए चिटठी लिखी थी। सीएमओ का कानपुर से तबादला नहीं किए जाने की बात भी लिखी गई थी लेकिन सीएम योगी ने संज्ञान लेकर सख्त एक्शन लेते हुए सीएमओ को सस्पेंड करने के साथ ईओडब्ल्यू जांच बैठा दी है, मामला भले ही शांत कराकर डीएम की जीत बताई जा रही है लेकिन चर्चा है कि मामले में अभी पिक्चर बाकी है।

कानपुर में डीएम-सीएमओ विवाद में चिटठियां लिखने से हुई माननीय की किरकिरी

» सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया और जांच बैठा दी गई

» सीएमओ मामले में जातीय भेदभाव बताकर विपक्ष दे रहा राजनीतिक हवा

सोमवार को यूपी के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक और सतीश महाना ने लखनउ में मुलाकात की। उसकी फोटो भी मीडिया में जारी की गई है। इस मुलाकात के अलग अलग ढंग से मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों कि बताया जाता है कि सस्पेंड सीएमओ नेमी, डिप्टी सीएम की गुडफेथ का था। उसके लिए सतीश महाना ने वीटो लगाया साथ ही समर्थन में एमएलसी अरूण पाठक, सुरेंद्र मैथानी से भी पत्र लिखवा गए लेकिन इसके बाद हरिदत्त नेमी पर बडी कार्रवाई हुई। इससे माननीयों की राजनीतिक किरकिरी हुई है। कानपुर महानगर में भाजपा नेता से लेकर कार्यकर्ता अलग-अलग धडों में बंटकर सोशल मीडिया में प्रलाप कर रहे हैं। इस कांड से कहीं न कहीं विधानसभा अध्यक्ष महाना के किरदार पर चोट लगी है, विपक्षी यहां तक कहकर चुटकी ले रहे हैं कि सरकार ने महाना को हल्का कर दिया। ऐसे में एक दिन पूर्व हुई नेताओं की मुलाकात से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अभी कोई गुल और खिलेगा। क्यों कि डा. नेमी ने प्रेस कांफ्रेस कर जातीय भेदभाव के साथ भ्रष्टाचार के आरोप डीएम पर लगाए थे, उसको लेकर सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि नेमी के दलित होने के कारण उसका उत्पीडन किया जा रहा है क्यों कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर जाति से आते हैं उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरधना विधायक अतुल प्रधान ने भी जातीय भेदभाद करने का आरोप लगाकर जांच की मांग की थी।

ऐसे में योगी सरकार भी किसी प्रकार के आरोपों को नहीं लेना चाहती है। ऐसे में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को भी हटाया जा सकता है। बीते दिन आरटीआई एक्टीविस्ट अमिताभ ठाकुर ने मामले में पत्र लिखकर डीएम के खिलाफ भी जांच किए जाने की मांग की है।

डीएम की जनता में मजबूत पकड़

डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह काफी लोकप्रिय हैं। जनसुनवाई में वह हर फरियादी की गंभीरता से बात सुनते हैं। इसी के चलते कलेक्ट्रेट में हर दिन शिकायतकर्ताओं की लंबी लाइन दिखती है।

हालांकि, जिस हिसाब से जितेंद्र प्रताप सिंह काम करते हैं उनके अधीनस्थ अधिकारी उतने ही उदासीन और लापरवाह रहते हैं। तहसीलों एवं ब्लाकों के छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है।

तहसील बनी मूकदर्शक, ग्राम सभा की भूमि पर हो रहा कब्जा

» एसडीएम के रोक के बावजूद दबंग करवा रहे हैं जबरन निर्माण कार्य

» ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों का कब्जा, ग्रामीणों ने की तत्काल कार्यवाही की मांग

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील स्थित ग्राम भज्जापुर में गांव के ही तमाम ग्रामीणों ने ग्राम समाज की भूमि पर तो रहे अवैध कब्जे को लेकर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया है कि सरकारी भूमि गाटा सं0 5 स्थित ग्राम भज्जापुर मजरा टोडरपुर के गांव में प्राचीन आस्था का केन्द्र दुर्गा माता का मंदिर है. जिससे गांव के लोगों की आस्था जुड़ी है और समस्त ग्राम वासी पूजा पाठ करते हैं एवं धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमे गांव के हजारो लोगों की भीड उमड़ती है।

उक्त आस्था के केन्द्र दुर्गा माता मन्दिर से लगी हई सरकारी भूमि गाटा सं0 05 स्थित है जो आम रास्ते के रूप में प्रयोग होती है। उसी से लगा हुआ उच्च प्राथमिक जूनियर विद्यालय है। जिससे नन्हें मुन्हे बच्चे अध्ययन के लिये जाते हैं। उसी उपरोक्त सरकारी भूमि पर गांव के ही दबंग गजराज सिंह पुत्र स्व0सुखलाल. सूरज सिंह पुत्र गजराज सिंह भगवान सिंह पुत्र गजराज, उदय यादव पुत्र गजराज निवासीगण ग्राम भज्जापुर तहसील व थाना भोगनीपुर अपनी दबंगी के बल पर उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा करने का निरन्तर प्रयास करते हैं। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण पूर्व में भी कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके है । उस पर उप जिलाधिकारी भोगनीपुर ने मौके पर लेखपाल व कानूनगो व पुलिस बल द्वारा निर्माण कार्य को रुकवा दिया था और भविष्य में निर्माण कार्य न करने की हिदायत दे दी थी लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उप जिलाअधिकारी के रोके जाने के बावजूद भी धीरे धीरे सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे है। निर्माण कार्य कराकर बन्द कर रहे हैं जिससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। 20 जून 2025 को उपरोक्त लोग उक्त सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे थे. जब प्रार्थीगण ने रोका तो उक्त लोग एक राय होकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और जबरन निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जिससे प्रार्थीगण भयभीत हैं यदि उक्त लोगो ने कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगणों के निकलने में घोर परेशानी का सामना करना पडेगा। उक्त लोग भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं और धनबल व जनबल के आधार पर सरकारी वेशकीमती भमि पर कब्जा कर रहे हैं। दबंगो के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है ।उन्होंने कहा कि मामला केवल ग्राम पंचायत की संपत्ति से नहीं है बल्कि मंदिर से जुड़ा हुआ आस्था का केंद्र है।

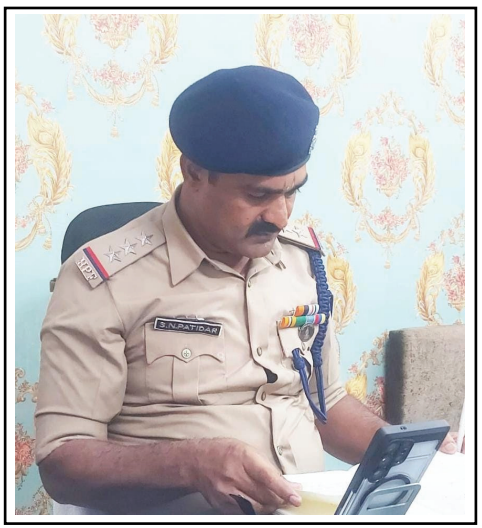

कानपुर सेंट्रल पर एस.एन. पाटीदार बने आरपीएफ पोस्ट प्रभारी

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर । सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के नए पोस्ट प्रभारी के रूप में एस.एन. पाटीदार ने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर अपनी सेवाएं दे रहे थे ।पदभार संभालने के बाद एस.एन. पाटीदार ने कहा कि फकानपुर सेंट्रल एक बड़ा और व्यस्त स्टेशन है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। यहां की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा ।उन्होंने बताया कि स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी। छोटी से छोटी शिकायतों पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाएगी और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन में अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे यात्री समय पर और सुरक्षित यात्रा कर सकें।

इसके अलावा जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त सहयोग से समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पाटीदार ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी का योगदान आवश्यक है।

सम्पादकीय

भाजपा की चिंता बढ़ाने वाले उपचुनाव नतीजे

भारतीय विपक्ष, जिसे इंडिया गठबंधन के रूप में बिखराव की स्थिति में माना जा रहा था, उसने गत उन्नीस जून को हुए उपचुनावों में, पांच में से चार सीटें जीत ली हैं। भाजपा पांच राज्यों में से सिर्फ एक सीट जीत सकी है। सबसे बड़ी उपलब्धि आप को हासिल हुई है, जिसने न केवल पंजाब की प्रतिष्ठित लुधियाना सीट जीती बल्कि मोदी–शाह के गढ़ में भी एक महत्वपूर्ण सीट जीतने में कामयाबी हासिल की है। गुजरात की विसावदर सीट जीती है, उस राज्य में जहां भाजपा तीन दशक से सत्ता में है। आप विधायक द्वारा पार्टी बदलने के बाद भाजपा को उम्मीद थी कि सीट उसकी झोली में आएगी, लेकिन आप ने इस झटके से उबरकर भाजपा उम्मीदवार को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आप ने पांच सीटें जीतकर भाजपा शासित राज्य में अपनी स्थिति मजबूत की थी। आमतौर पर उपचुनाव सत्तारूढ़ दल की पार्टी ही जीतती रही है, जैसा कि पंजाब में लुधियाना पश्चिम सीट आप ने तथा पश्चिम बंगाल में कालिगंज सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं केरल में उलट–फेर करते हुए कांग्रेस गठबंधन सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एलडीएफ से नीलाम्बुर सीट छीनने में सफल रहा। ऐसे समय में यह चिंता की बात है जब विधानसभा चुनाव में एक साल से कम समय रह गया है। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। हाई–प्रोफाइल और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिये पार्टी ने आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन पार्टी का कहना है कि वे स्टार अभियान चलाने वालों में सूचीबद्ध रहे हैं। दरअसल, थरूर के पार्टी हाईकमान से उस समय मतभेद उजागर हुए थे जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिये विदेशों में चलाए गए बहु–पार्टी अभियान में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भविष्य बताएगा कि आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थरूर को कांग्रेस कैसे संभालती है।

बहरहाल, केरल व पश्चिम बंगाल के उपचुनावों की विफलता ने भाजपा को परेशान जरूर किया होगा। जो इन विपक्ष के अंतिम गढ़ों में सत्ता की बाट जोह रही है। हालांकि, उस भाजपा को कमतर आंकना भूल होगी, जो हर बाधा को पार करने की कला जानती है। बहरहाल, पंजाब में आप ने लुधियाना पश्चिम सीट जीतकर कई समीकरण साधे हैं। यह जीत सिर्फ मध्यावधि चुनाव की जीत नहीं है बल्कि पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाने वाली जीत है। आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की कांग्रेस के अनुभवी नेता भारत भूषण आशु पर 10,637 मतों की निर्णायक जीत शहरी क्षेत्रों में आप की पकड़ को दर्शाती है।

आत्मनिर्भरता से रक्षा निर्यातक बनने के बीच चुनौती

मुकुल व्यास

रक्षा निर्यात न केवल विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया है, बल्कि हमारी वैश्विक रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करता है। भारत की 'सॉफ्ट पॉवर' और 'स्ट्रैटेजिक पॉवर' को बढ़ावा मिलता है।वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां रूस-यूक्रेन, इस्राइल-हमास और इस्राइल-ईरान जैसे युद्ध चल रहे हैं, वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भी सैन्य तैयारी की गंभीरता को रेखांकित किया है। ऐसे माहौल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर विश्व का ध्यान केंद्रित हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आयातक से निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ता भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों ने देश के रक्षा निर्माण और निर्यात को गति दी है।रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 1,521 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

यह लगभग 950 प्रतिशत की वृद्धि है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब रक्षा निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख रक्षा उत्पादों में आर्टिलरी गन सिस्टम्स (धनुष) आकाश मिसाइल प्रणाली, राडार सिस्टम्स (स्वाति राडार), गश्ती नौकाएं और मिसाइल बोट्स, डोर्नियर एयरक्राफ्ट, 'ध्रुव', बुलेटप्रूफ जैकेट्स, हेल्मेट्स, स्मॉल आर्म्स और गोला–बारूद, ड्रोन, यूएवी आदि शामिल हैं। सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं मसलन रक्षा उत्पादन नीति, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन, विदेशों में रक्षा अटेचेज़ की नियुक्ति, सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिफेंस एक्सपो जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ–साथ टाटा, एल एंड टी, भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियों ने डिफेंस निर्यात को नया आयाम दिया है। सरकार ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे निजी कंपनियां भी रक्षा उत्पादन और निर्यात में भाग ले सकें। रक्षा निर्यात से जुड़े लाइसेंस और परमिशन अब सिंगल विंडो सिस्टम से मिल रहे हैं।ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा तकनीक की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस' द्वारा विकसित की गई है।

क्योंकि इससे भारत विश्व के चुनींदा मिसाइल निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया है।जनवरी, 2022 में, भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 375 मिलियन डॉलर (करीब 2700 करोड़ रुपये) का सौदा किया। इस सौदे के तहत भारत शिप–लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति कर रहा है। यह भारत की पहली बड़ी मिसाइल निर्यात डील है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि देशों को — (संभावित ग्राहक) भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की है। ब्रह्मोस के 'लैंड, शिप और एयर वर्ज़न' को लेकर इन देशों में रुचि जताई गई है।

फेक नैरेटिव के दौर में सिसकती इंसानियत

रूस–यूक्रेन युद्ध

सुचिता खन्ना

इस समय एआई द्वारा तैयार युद्ध के फेक वीडियोज और रील्स की बाढ़ आ गई है। आम लोगों के लिये समझना मुश्किल है कि सच क्या है। इस फेक नैरेटिव से लड़ना वाकई मुश्किल काम है।

इस्राइल-ईरान युद्ध के खात्मे का इंतजार दुनिया को था कि विश्व का दरोगा अमेरिका इसमें कूद पड़ा। दुनिया पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध से परेशान थी, इस बीच भारत-पाकिस्तान के बीच भी कुछ दिनों का युद्ध हो चुका था। अमेरिका का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। ईरान पर बम बरसाने से पहले अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि वह फौरन इसे रोके। यह बात बिल्कुल ठीक है कि परमाणु अस्त्र पूरी मानवता के लिए आफत की तरह हैं।

जापान के हिरोशिमा–नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, उनकी विनाशक क्षमता आज के परमाणु हथियारों के मुकाबले बहुत कम थी। तब भी जापान ने इसे दशकों तक भुगता। आज तो ऐसे हथियार हैं, जो पल भर में दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ऐसे में हे अमेरिकियों, जितने मारक हथियारों के जखीरे आपके पास हैं, दूसरे देशों को उपदेश देने से पहले, उन्हें नष्ट क्यों नहीं कर देते। क्या वे दुनिया के लिए खतरा नहीं हैं?या कि उसी तर्क पर चलते हो कि जबरा मारे और रोने भी न दे।

जब अमेरिका के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं, तब इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ईरान का पक्ष लिया जा रहा है। मानव अधिकारों के मामले में ईरान की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। दशकों पहले जब ईरान के इस्लामिक आंदोलन ने शाह रजा पहलवी को खदेड़ दिया था और पेरिस में निर्वासित जीवन बिताने वाले खोमेनी को हाथो हाथ लिया था, तब की याद आती है। खोमेनी के पक्ष में वहां जो युवा शाह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनमें से बहुत से खुद को इस्लामिक मार्क्सिस्ट कहते थे। जब खोमेनी पेरिस से लौटे, तो उनकी कार को कंधे पर उठा लिया गया था। बाद में सबसे पहले खोमेनी ने इन्हीं इस्लामिक मार्क्सिस्ट कहने वाले लोगों को सरेआम मौत के घाट उतरवाया था। शाह ने स्त्रियों को घर की चारदीवारी से निकाला था,

उन्हें आत्मनिर्भरता की राह दिखाई थी, खोमेनी ने उन्हें वापस सदियों पहले की स्थिति में धकेल दिया।

अब वहां स्त्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकतीं। न बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, न बिना माता–पिता की लिखित अनुमति के पढ़ सकती हैं, न नौकरी कर सकती हैं। न शादी ही। सिर से हिजाब जरा–सा खिसका नहीं कि आफत आई नहीं। अफगानिस्तान की तरह ही वहां भी स्त्रियों को मामूली मानव अधिकार नहीं हैं। इसे धर्म और हमारी संस्कृति कहकर रफा–दफा कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका जिसका ट्रेक रिकॉर्ड दुनिया भर के तानाशाहों को पालना–पोसना रहा है, वह मनमाने तरीके से मानव अधिकारों की व्याख्या करता है। चाहे डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकंस, उनकी नजर सिर्फ अपने यहां पूंजीपतियों के हितों को देखने की होती है। मानव अधिकार आदि की बातें तो दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं।

इस सिलसिले में जान पर्किन्स की मशहूर पुस्तक 'कन्फेशन्स ऑफ़ ऐन इकोनॉमिक हिटमैन' पढ़ी जा सकती है। जान खुद इकोनामिक हिटमैन रहे हैं यानी कि दूसरे देशों में अमेरिकी पूंजीपतियों के हितों को हर हाल में संरक्षित करने वाले।

फिर दूसरा देश अपने यहां क्या करना चाहता है, इसमें दखल देने वाले आप कौन हैं। अमेरिका अपने यहां कौन से हथियार विकसित कर रहा है, यदि किसी दूसरे देश को यह बात पसंद न आए तो क्या वह अमेरिका पर उसी तरह हमला कर दे, जैसे अमेरिका करता है। कल अगर भारत की सत्ता आपकी बात न माने, तो आप उस पर भी चढ़ दौड़ेंगे। ये बात अलग है कि कभी वियतनाम से पिटेंगे, तो कभी अफगानिस्तान से सिर पर पांव रखकर भागेंगे।

आपको नब्बे का दशक याद होगा। अमेरिका, ईराक पर टूट पड़ा था। बहाना बनाया था कि ईराक के पास ऐसे रासायनिक हथियार हैं, जो विश्व को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह कभी प्रमाणित नहीं हो सका। लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उनका वह चित्र छपा था, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनका सिर एक ओर पड़ा था और धड़ एक ओर।

नब्बे के दशक में ही भारत में टेलीविजन घर–घर पहुंच चुका था। ईराक, अमेरिका की लड़ाई का पहली बार लाइव प्रसारण लोगों ने घर बैठकर देखा था और रोमांचित हुए थे। आज इक्कीसवीं सदी के पचीसवें वर्ष में इस्राइल, अमेरिका, ईरान युद्ध की तस्वीरें, लाइव प्रसारण भी खूब दिख रहे हैं।

बीबीसी और न्यूयार्क टाइम्स ने बताया कि इस समय युद्ध के फेक वीडियोज और रील्स की बाढ़ आ गई है। इन्हें एआई द्वारा तैयार किया गया है। इन रील्स और वीडियोज को देखने वालों और फालोअर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। इस फेक नैरेटिव से लड़ना वाकई मुश्किल काम है।

भारत में पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन
एक गंभीर विश्लेषण

शिखर, अधिवक्ता
उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ।

भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संवैधानिक रूप से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, पुलिस क्रूरता, हिरासत में मौतें, गैरकानूनी गिरफ्तारियां और अत्यधिक बल प्रयोग की घटनाओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आचरण को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। जहां पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अनिवार्य भूमिका निभाती है, वहीं उनके कुछ तरीके उन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें वे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। भारतीय संदर्भ में मानवाधिकारों की समझ भारत में मानवाधिकार निम्नलिखित के तहत सुनिश्चित हैं

भारत का संविधान - विशेषकर अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), और 22 (मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा)

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों - भारत कई सम्मेलनों का सदस्य है, जिनमें विश्व मानवाधिकार घोषणा (और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय संधि शामिल हैं।

इन कानूनी सुरक्षा के बावजूद, पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन एक बार-बार सामने आने वाली समस्या बनी हुई है।

पुलिस से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों के प्रकार

1. हिरासत में मौतें और यातना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, हर साल सैकड़ों हिरासत में मौतें दर्ज होती हैं, जिनमें से कई यातना के कारण होती हैं।

2020 में तमिलनाडु में जयराज और बेनिक्स की हिरासत में हुई मौतों ने प्रणालीगत दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी को उजागर किया।

2. गैरकानूनी गिरफ्तारी और हिरासत

पुलिस अक्सर वारंट के बिना गिरफ्तारियां करती है, संदिग्धों को अनुमत सीमा से अधिक समय तक हिरासत में रखती है, और 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करती, जो संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है।

3. नकली मुठभेड़

न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए मुठभेड़ के नाम पर की जाने वाली गैरकानूनी हत्याओं की अक्सर आलोचना होती है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि ये घटनाएं मंचित होती हैं।

उदाहरण- 2019 की हैदराबाद रेप केस में पुलिस ने चार आरोपियों को कथित मुठभेड़ में मार दिया, जिसे आलोचना और प्रशंसा दोनों मिली।

4. विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग

शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अक्सर अनुपातहीन बल प्रयोग किया जाता है, जिससे चोटें और मौतें होती हैं। किसान आंदोलन (2020-2021) और सीएए-एनआरसी विरोध इसके हालिया उदाहरण हैं।

5. भेदभावपूर्ण पुलिसिंग

दलित, मुस्लिम, आदिवासी और एलजीबीटी+ समुदाय जैसे वंचित वर्गों के साथ पुलिस द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जाति-आधारित हिंसा और धार्मिक प्रोफाइलिंग के मामले अच्छी तरह से दर्ज हैं।

मानवाधिकार उल्लंघनों के पीछे के कारण

1. औपनिवेशिक विरासत

भारत की पुलिस प्रणाली अभी भी मुख्यतः 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत काम करती है, जो ब्रिटिश शासन ने जनता पर नियंत्रण और दमन के लिए बनाया था।

2. जवाबदेही की कमी

आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र कमजोर हैं। पुलिस अक्सर राजनीतिक संरक्षण और स्वतंत्र निगरानी की कमी के कारण बिना जवाबदेही के काम करती है।

3. प्रशिक्षण और कार्य परिस्थितियों की खराबी

मानवाधिकारों में अपर्याप्त प्रशिक्षण और अत्यधिक भार वाले कार्यस्थल से अधिकारियों में तनाव और प्रतिक्रियाशील आक्रामकता बढ़ती है।

4. राजनीतिक हस्तक्षेप

पुलिस को राजनीतिक मनमानेपन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और लक्षित उत्पीड़न होता है।

5. न्याय प्रणाली में देरी

अधिभारित अदालतें और लम्बे मुकदमे पीड़ितों को न्याय मांगने से हतोत्साहित करते हैं, जो उल्लंघनों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है।

कानूनी और संस्थागत तंत्र

1. न्यायिक सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में हिरासत में यातना रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं।

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में कोर्ट ने पुलिस सुधारों का आदेश दिया, जिसमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना और जांच को कानून एवं व्यवस्था के कार्यों से अलग करना शामिल है।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग -अधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और मुआवजे की सिफारिश करता है, हालांकि इसके आदेश अनुशंसात्मक होते हैं, बाध्यकारी नहीं।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम

नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से पुलिसिंग प्रथाओं में पारदर्शिता मांग सकते हैं, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अक्सर छूट का दावा किया जाता है।

पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने में चुनौतियां

न्यायिक निर्देशों का कमजोर प्रवर्तन

अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र के प्रति सीमित जनजागरूकता

पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में हिचकिचाहट

पुलिस के खिलाफ मामलों में निचली सजा दरें

सुधार के लिए सिफारिशें

1. पुलिस सुधारों को लागू करें

औपनिवेशिक कानूनों को लोकतांत्रिक, जनता-केंद्रित पुलिसिंग मॉडलों से बदलें और आधुनिकीकरण करें।

पुलिस को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करें।

2. निगरानी निकायों को सशक्त बनाएं

? ह॥त्रष्ट और राज्य मानवाधिकार आयोगों को बाध्यकारी शक्तियां दें।

? सभी राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को सक्रिय करें।

3. प्रशिक्षण और संवेदनशीलता

पुलिस के सभी रैंकों के लिए अनिवार्य मानवाधिकार प्रशिक्षण लागू करें।

विश्वास बनाने के लिए समुदाय-आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दें।

4. तकनीक और पारदर्शिता

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बॉडी कैमरे, पुलिस थानों में सीसीटीवी और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग का अनिवार्य उपयोग करें।

5. हिरासत में यातना के खिलाफ कानून बनाएं

भारत को संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी संधि को अनुमोदित करना चाहिए और व्यापक यातना विरोधी कानून पारित करना चाहिए।

-निष्कर्ष-

जहां भारत का लोकतांत्रिक ढांचा मानवाधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं पुलिस द्वारा होने वाले उल्लंघन एक गंभीर विरोधाभास हैं। आवश्यक है कि पुलिसिंग प्रणाली का समग्र परिवर्तन हो- दबाव और नियंत्रण से हटकर जवाबदेह सेवा की ओर। वास्तविक सुधारों के बिना, कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास घटता रहेगा, जिससे कानून का शासन और लोकतांत्रिक शासन कमजोर होगा।

भाजपा नेता के घर जाँच करने पहुँचे एडीसीपी

» बाहर घूमने गए भाजपा नेता के बंद घर में लाखों की चोरी का मामला

» तीन टीमें घटना का खुलासा करने को लगी

» आसपास के खंगाले जा सीसीटीवी कैमरे

स्वराज इंसान संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। बंद पड़े भाजपा नेता के मकान में शनिवार को हुई लाखों की चोरी की मामले में सोमवार एडीसीपी भाजपा नेता के घर पहुँचे और घर के हर कोने तथा आसपास बारीकी से जाँच की। एडीसीपी ने जल्द ही घटना के खुलासे का दावा किया है। घटना का खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें काम कर रही हैं। उधर वकीलों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है।

मालूम हो कि बाहर पहाड़ी इलाकों में परिवार व दोस्तों संग घूमने गए वरिष्ठ भाजपा नेता का शांति नगर मोहल्ला स्थित मकान है।

वह 20 जून को मकान बंद कर अपने ड्राइवर रामशरण को घर की देखभाल करने को कहकर परिवार व दोस्तों संग बाहर पहाड़ी इलाकों में घूमने गए थे। ड्राइवर रामशरण विक्रम मिश्रा का भरोसेमंद आदमी है। घर की देखरेख की

जिम्मेदारी लिए ड्राइवर रामशरण रोज शाम होते घर की लाइट खोलने तथा सुबह बंद करने जाता था।

शनिवार शाम वह लाइट खोलने गया तो उसे चोरी की जानकारी हुई। जिसके बाद पुलिस व फॉरेनसिक टीम ने मौके पर जाकर छानबीन की। सोमवार को एडीसीपी कपिल कुमार इंस्पेक्टर अशोक कुमार को लेकर विक्रम मिश्रा के घर पहुँचकर जांच की। बता दें कि मामले का खुलासा करने के लिए तीन टीमें लगी हैं। आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस दावा कर रही है चोरी की घटना का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा।

---स्वराज इंडिया की खबर का असर---

बिल्हौर तहसील में पानी की बहाली, नए एसडीएम ने खुद लिया संज्ञान

» कुछ ही देर में पकड़ लिया गया फाल्ट

» बीते तीन सप्ताह से तकनीकी खराबी के कारण, सुख चुकी थी टंकी

» स्वराज इंडिया अख़बार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। बीते तीन हफ्तों की प्यास, विभागीय लापरवाही और जनता की बेबसी के बाद आखिरकार स्वराज इंडिया की खबर ने अपना असर दिखाया। तहसील परिसर में तकनीकी फाल्ट के कारण खराब पड़ी पानी की मोटर को नया जीवन मिला और इसके पीछे थे नए एसडीएम ज्वाला प्रसाद , जिन्होंने न सिर्फ गंभीरता समझी बल्कि तत्काल फॉल्ट को ठीक करवाने का आदेश दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि आनन–फानन में टेक्नीशियन को बुलवाया गया और पानी की टंकी का फाल्ट सही कराया गया।पानी की एक–एक बूंद के लिए

तरसते लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं वो बुजुर्ग जो कल तक सूखे नल को ताक रहे थे, आज उसी से पानी पीते दिखे। मालूम हो कि तकनीकी खराबी के कारण तहसील परिसर में बनी टंकी कई दिनों तक शो–पीस बनी रही। वकीलों से लेकर तहसील का स्टाफ, वादकारी, आम लोग, सभी बूंद–बूंद पानी को तरसते रहे।लोग अपनी जेब ढीली कर पानी खरीद कर पीते दिखे। ज़ब आवाज बनी

बिल्हौर तहसील परिसर में गहराया पेयजल संकट, मोटर खराब, लोग बूंद-बूंद पानी को तरसे

» दो सप्ताह बाद भी नहीं किया गया कोई प्रयास

» पीने के पानी के लिए दूर दूर तक भटक रहे लोग

स्वराज इंडिया न्यूज

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील परिसर में पिछले दो सप्ताह से जलापूर्ति ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय लोग और तहसील आने वाले फरियादी पीने के पानी के लिए परेशान हैं। तहसील में लगा मुख्य मोटर खराब होने के कारण पानी की टंकी नहीं भर पा रही है। जिसके कारण पूरे तहसील परिसर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। जगह-जगह लगे वाटर कूलर सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी ही नहीं आ रहा है।इस गंभीर पेयजल संकट से तहसील कर्मचारी, वकील, और दूर-दराज से अपनी शिकायतें लेकर आने वाले फरियादियों को जूझना पड़ रहा है। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए या तो बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है या फिर दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है।

दो दिन पहले ही नए एसडीएम ने चार्ज संभाला था। उनके सामने यह समस्या रखी गई थी। जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द इसका समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। जलापूर्ति जैसी समस्या पर जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और निष्क्रियता प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।वकीलों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मोटर की मरम्मत कराने और तहसील में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं बार एसोसिएशन बिल्हौर के महामंत्री महेंद्र कुशवाहा ने कहा है बीते कई दिनों से तहसील में पानी की किल्लत है, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए।

FOLLOW UP

बजट नहीं है तो फिर कैसे सही होगा मोटर!

बिल्हौर। यदि तहसील के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो इस मद में कोई बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में मोटर कौन सी कराएगा और किस मद से सही कराएगा। यह यक्ष प्रश्न है। जिसका जवाब समय के गर्त में है। बताया जाता है कि इस मद में जल्दी बजट नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह समस्या और भी गहरा सकती है।

ख़बर तो हरकत में सिस्टम आया और अब फिर जीवन की धारा बहने लगी।

बुजुर्ग की तस्वीर ने बताया- व्यवस्था जब जागे,तो देर नहीं लगती

तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर टंकी के नल से झुककर पानी पीते बुजुर्ग की यह तस्वीर केवल एक क्षण नहीं,यह व्यवस्था पर भरोसे की वापसी की तस्वीर है। यह वो तस्वीर है जो बताती है कि व्यवस्था ज़ब जागे तो देर नहीं लगती।

जनता की आवाज बनी स्वराज इंडिया की रिपोर्टिंग

बीते तीन सप्ताह से पानी संकट से जूझते लोग और जिम्मेदरों की चुप्पी फिर ख़बर ने सब बदल दिया। अब जब पानी बह रहा है तो लोगों में राहत है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि पत्रकारिता ऐसी ही हो,जो सिर्फ खबर न हो, असर भी छोड़ जाए।

हैदरपुर इलाके में सामुदायिक शौचालय बने शो पीस

» शौचालय में ताला बंद, पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं

स्वराज इंडिया संवाददाता

हैदरगढ़ बारांबकी। विकास खंड हैदरगढ़ क्षेत्र के जारमऊ गांव में लाखों रुपए की लागत से बना सार्वजनिक शौचालय बेकार पड़ा है। पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय में पानी सप्लाई के लिए लगा मोटर कई महीनों से खराब है। इस कारण पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। पानी की व्यवस्था न होने से शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है। देखरेख और रखरखाव के अभाव में शौचालय की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। शौचालय की फर्श कई जगहों से टूट चुकी है। स्थिति यह है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहां जांच के लिए नहीं आता है ग्राम प्रधान जयराम के अनुसार, पंचायत सचिव के स्थानांतरण के कारण शौचालय की मरम्मत नहीं हो पाई है। उन्होंने जल्द ही मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि यह शौचालय गांव को खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल साबित हो रहा है।

उपखंड अधिकारी को दी कर्मियों ने भावभीनी विदाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जैदपुर बाराबंकी। विद्युत उपखंड में सोमवार को भावुक माहौल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दो वर्षों तक सेवा देने वाले उपखंड अधिकारी संदीप सिंह का विभागीय स्थानांतरण हो गया है।

सफदरगंज और जैदपुर के अवर अभियंताओं सहित कर्मचारियों ने फूल मालाओं से उनकी विदाई की। इसी अवसर पर नव नियुक्त उपखंड अधिकारी शिवेंद्र कुमार का भी स्वागत किया गया।

विदाई समारोह में संदीप सिंह ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हटाए गए कर्मचारियों के समायोजन के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने नए एसडीओ के साथ मिलकर काम करने और सेवाओं को बेहतर बनाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में जेई मिर्जा परवेज हुसैन, जेई शमसुल लका अंसारी, सफदरगंज से जेई दीपक कुमार, सुपरवाइजर अमन यादव, वकार मेहंदी, सुरेंद कुमार,सुशील कुमार,समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। भावुक क्षणों में एसडीओ संदीप सिंह ने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

विद्यालय के सामने गंदा पानी, गांव में विकास बेमानी

» एसडीम से शिक़ायत लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। तालाब में जाने वाले गंदे पानी को नाली बंद करके रोक दिया गया अब गांव के खड़ंजे पर विद्यालय के सामने गंदा पानी भरा है। जिससे ग्रामीणों को भारी दुश्वारियां का सामना करना पड़ रहा है। गांव के दर्जनों लोगों ने इसकी शिकायत एसडीम से की लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। विकासखंड रामनगर के ग्राम अतरौली निवासी दुर्गेश कुमार कमलेश जगदीश सुरेंद्र अर्जुन राजकुमार आदि ने एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कहां है कि करीब 25 वर्षों से सभी लोगों के घरों का गंदा पानी सोनेलाल के घर से होकर कच्ची नाली के माध्यम से गांव के समदा तालाब में जाता था जिसके बंद हो जाने के चलते गंदा पानी अब खड़ंजा पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सामने भरा रहा है। बंद नाली को पुनः खोलने की बात पर गाँव के राजू देशराज द्वारा धमकी दी जा रही है। मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों को गंदे पानी के बीच से होकर निकलना पड़ता है। यदि समय रहते समस्या का निदान नहीं किया गया तो विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को भी परेशानियों से जूझना पड़ेगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

आयुक्त के आदेश की भी उड़ाई धज्जियां, 100 मीटर सड़क के लिए जनता तरसी

» मुख्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी ने ठुकराया आयुक्त ग्राम विकास का स्पष्ट निर्देश

» फरियादियों पर हो रही दबंगई, प्रधान की साजिश में फंसाए जा रहे आम लोग

उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के यहां शिकायत करता फरियादी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र की एक बस्ती के लोग 100 मीटर सड़क के निर्माण के लिए आठ माह से प्रशासनिक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है।

आयुक्त ग्राम विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी ने बीलापुर गांव में दौरे के दौरान स्पष्ट आदेश दिए थे कि यह कार्य अवश्य कराया जाए। लेकिन न तो मुख्य विकास अधिकारी और न ही खंड विकास अधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया।

लोगों का कहना है कि उन्होंने जिलाधिकारी, उपमुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, मगर नतीजा शून्य रहा। यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस तरह जमीनी स्तर पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं।

फरियादियों को बनाया जा रहा निशाना, साजिशें हो रही तेज

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर बार-बार अफसरों से संपर्क करते हैं, तो गांव के कुछ दबंग प्रधान और उनके सहयोगी फरियादियों को झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिशें करते हैं। फर्जी शिकायतें करवा कर उन्हें चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं।

पीड़ितों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक केवल कागजों में योजनाएं दौड़ रही हैं, धरातल पर विकास नहीं हो रहा। जनता ना सिर्फ भटक रही है, बल्कि अधिकारियों की बेरुखी का शिकार बनकर हंसी का पात्र भी बन रही है।

बरौर मंडल की भाजपा कार्यकारिणी घोषित, पदाधिकारियों को मिला दायित्व

» जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने पदाधिकारियों को पहनाया पटका, दी शुभकामनाएं

» कार्यकारिणी के 16 पदों में से एक पद रिक्त, जल्द होगा मनोनयन

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। भाजपा बरौर मंडल में संगठन विस्तार के तहत मंडल अध्यक्ष महेश संखवार ने 16 सदस्यीय नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला कार्यालय माती में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को पटका पहनाकर नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी। उन्होंने संगठन के कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

टीम में उपाध्यक्ष बनाए गए अनुज अवस्थी, अंकित शुक्ला, रणजीत सिंह पटेल, अशोक दोहरे, वकील सिंह नायक और दिलीप शंकर दिवाकर। महामंत्री बने अक्षय कुमार व शुभम सचान। मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई अनिल कमल, शिवम बाल्मीकि, अवध द्विवेदी, रूचि त्रिपाठी और अनीता सविता को। कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए अवधेश अवस्थी। मंत्री का एक पद अभी रिक्त है।

इस अवसर पर भाजपा नेता शिवप्रसाद मिश्रा, बबलू शुक्ला, सौरभ मिश्रा, सत्यम सिंह चौहान, अनिरुद्ध सिंह, देवेश तिवारी, पंकज सचान और दीपक सेन सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

श्री गौरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED HOSPITAL)
यू.पी.एस.आई.डी.सी. जैनपुर, कानपुर देहात
Mob: 9710106661, 7310106662, 7310106663
अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन, डिजिटल एक्सरे की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध
- आई0सी0यू0/सी0सी0यू0।
- वेंटीलेटर, ए0वी0जी0ए0, कारडियक मॉनीटर, मल्टीपैरा मॉनीटर की सुविधा।
- C-Arm युक्त वतानुकूलित ऑपरेशन थियेटर।
- ट्रामा स्पोर्ट हेड इन्जुरी का सफल इलाज।
- डिजिटल एक्स.रे, सी.टी. स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड (U.S.G.) की सुविधा

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज उपलब्ध है।
टी.पी.ए. कैशलेस की सुविधा उपलब्ध
उपलब्ध सुविधाएं:- ए0बीजी0ए0 मशीन
1. अत्यंत कम वजन के नवजात शिशु एवं समय से पहले जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल। 2. नवजात एवं बाल्य गहन चिकित्सा इकाई ;च्ण्ब्न्ण्द्ध 3. चौबीस घंटे मेडिकल स्टोर, एक्सरे, पैथालॉजी, कैन्टीन की सुविधा। 4. नि:शुल्क एम्बुलेंस की सुविधा। 5. दूरबीन द्वारा पित्त एवं गुर्दे, यूरेटर की पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। 6. गहन चिकित्सा इकाई, वेंटीलेटर सुविधा सहित। 7. सभी प्रकार के हड्डी रोग एवं ट्रामा सम्बंधित ऑपरेशन। 8. सिजेरियन ऑपरेशन/डिलेवरी/बच्चेदानी का ऑपरेशन अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर। 9. कार्डियक मीनीटरिंग/इको कार्डियोग्राफी/सोनोग्राफी/टी.एम.टी.
डा. संजय त्रिपाठी
एम.बी.बी.एस., एमडी मेडिसिन
फेलोशिप क्रिटिकल केयर
विजय बाजपेई
मैनेजिंग डायरेक्टर

युवा किसान की खेत में निर्मम हत्या

पूरा मामला खून से सना – ट्यूबवेल की गड़गड़ाहट के बीच रात में चारपाई पर थम गई नागेंद्र की सांसें

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। धान की फसल की उम्मीदों के साथ खेत की सिंचाई कर रहे एक युवा किसान की जान खेत में ही ले ली गई। मामला थाना पूराकलंदर के पलिया गांव का है, जहां 28 वर्षीय नागेंद्र यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। नागेंद्र, जिला जज के रिटायर्ड ड्राइवर राम प्रकाश यादव का इकलौता बेटा था।

सूत्रों के मुताबिक, नागेंद्र मंगलवार की रात ट्यूबवेल चालू करके खेत की सिंचाई कर रहा था।

थकान के चलते वह खेत में ही रखी चारपाई पर सो गया। लेकिन सुबह जब लोग खेत की ओर पहुंचे, तो चारपाई पर नागेंद्र का रक्तरंजित शव देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

मृतक की फाइल फोटो

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है।

इस खौफनाक वारदात ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है, वहीं किसान परिवार अपने इकलौते बेटे को खोकर बेसुध है। अब सवाल उठता है—क्या यह पुरानी रंजिश थी या खेत की उपजाऊ जमीन किसी की आँखों में खटक रही थी?

एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि सुबह साढ़े पांच बजे नागेंद्र यादव (40) की हत्या कर दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गयी है। सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं

स्वराज इंडिया न्यूज यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समाधान प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय मिले। उन्होंने पुलिस, राजस्व, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर तत्पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में महिला, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग उपस्थित रहे।

ब्राह्मण बनकर कथा सुनाने पहुंचे कथावाचक की जमकर पिटाई

» दो आधार कार्ड मिले, एक में अग्निहोत्री, दूसरे में सिंह लिखा था

» मूत्र छिड़कने, नाक रगड़वाने और सोने की चेन छीनने का गंभीर आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इटावा। बकेवर के दादरपुर गांव में शनिवार रात एक कथावाचक पर ब्राह्मण न होते हुए भी कथा वाचन करने और झूठी पहचान बताने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने न केवल पिटाई कर दी, बल्कि उसे अपमानित भी किया। कथावाचक मुकुट मणि यादव, जो खुद को मुकुट मणि अग्निहोत्री बता रहे थे, जब उनके दो आधार कार्ड में एक पर यादव और दूसरे पर अग्निहोत्री लिखा मिला, तो ग्रामीणों का शक गहरा गया। पूछताछ में कथावाचक ने यादव होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद कथित रूप से उनके साथ मारपीट की गई, चोटी काटी गई और परीक्षित की पत्नी के सामने नाक रगड़कर माफी मंगवाई गई।

अपमान और हिंसा की हदें पार, पुलिस जांच में जुटीकथावाचक और उनके दो सहयोगियों संत सिंह यादव और नालवादक श्याम कठेरिया को कथित रूप से न सिर्फ पीटा गया, बल्कि 25 हजार रुपये जुर्माने के नाम पर वसूले गए और दो तोले की सोने की चेन भी छीन ली गई। कथावाचक के अनुसार, उनके ऊपर मानव मूत्र तक छिड़का गया और गंगाजल से पांव धुलवाए गए। घटना का वीडियो सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से मामला दर्ज कर लिया। एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव के अनुसार, 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें चार की गिरफ्तारी हो चुकी है। वीडियो को भी साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया गया है।

ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पं.अरुण दुबे ने शक्ति धाम बैंकट हॉल में प्रेस कोंफ्रेंस कर कहा कि दाँदरपुर में हुयी घटना पर ब्राह्मण महासभा अपना पक्ष रखेगी। अभी प्रशासन व मीडिया ने सिर्फ एक पक्ष की बात क़ो सुना है , न्याय व निष्कर्ष तक तभी पहुंचा जा सकता है ज़ब दोनों पक्षो की बात सुनी जाये , दाँदरपुर से पीड़ित परिवार भी इटावा पहुंचकर स्स्ककइटावा के समक्ष अपनी बात रखेगा । उन्होंने कहा की किसी के भागवत कथा और पूजा पाठ करने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जाति छुपाने पर विवाद हुआ है। इसपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कथा वाचक के पास से बरामद किए गए आधार कार्ड

भागवत कथा करने से कोई आपत्ति नहीं सिर्फ जाति छुपाने से हुआ विवाद

अयोध्या विकास प्राधिकरण में दलाली का ब्लूप्रिंट

» घोषणा सीएम की,नियम जेई का-रामराज में अफसरशाही ही भगवान

» विकास के नक्शे में चाय पानी की स्याही से तय होता है प्लाट का भविष्य

» रामनगरी की इमारते आस्था से नही अफसरों की मर्जी से खड़ी होती है

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऽभवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 योजना की घोषणा ने आम जनता के चेहरे पर थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन अयोध्या विकास प्राधिकरण के अफसरों ने उस उम्मीद को फाइलों में कैद कर दिया है। योगी जी ने कहा था–1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास नहीं कराना होगा, कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन रामनगरी में राजाज्ञा भी जेई की मर्जी से चलती है!नगर निगम क्षेत्र में रवि साहू ने 800 वर्गफीट की भूमि खरीदी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर भरोसा करके मकान निर्माण शुरू किया। बैंक ने ऋण भी स्वीकृत कर दिया। लेकिन विकास प्राधिकरण के 'चौकन्ने' जेई चन्दन गुप्ता को ये सब नागवार गुज़रा। उन्होंने न सिर्फ निर्माण रुकवाया, बल्कि 1200 वर्गफीट की काल्पनिक रिपोर्ट बना डाली। दूसरे मकान की फोटो जोड़कर एक धमकी भरी नोटिस रवि को थमा दी–क्यों न निर्माण गिरा दिया जाए?

बड़ा सवाल उठता है ?

अगर सीएम की घोषणा का आदेश नहीं आया था, तो बैंक को लोन किस आधार पर मिला? और अगर आदेश नहीं आया था, तो जेई ने झूठी फोटो और फर्जी स्केल का सहारा क्यों लिया?

यह न तो सिफ़र की गलती है, न कोई तकनीकी भ्रम। यह वही 'सिस्टम' है, जिसमें फाइलें चाय की प्याली पर चलती हैं, और नियम जेई की जेब में रखे जाते हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता भी अब अफसरशाही की ढीठ व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं—क्योंकि जब जेई क्लिक कर दे, तो मुख्यमंत्री की क्लिक भी डिलीट हो जाती है।

स्वराज इंडिया का मानना है कि–

प्राधिकरण का यह विकास मॉडल अब नई परिभाषा लिख रहा है—जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का निर्माण, और ईमानदार लोगों का विध्वंस। मतलब की जब तक शासनादेश प्राधिकरण की 'सुविधा' के अनुसार न आए, तब तक रामनगरी में केवल भ्रष्टाचार का नक्शा ही पास होगा।सरकार की मंशा को लागू ना करने के लिए अयोध्या बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र ने विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री की घोषणा

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पत्रांक/ 2261 /अ0वि0प्रा0अ0/प्रवर्तन/2025–26 दिनांक/17-6-2025

नोटिस

श्री रवि साहू,
देवकाली मंदिर के पीछे, बेनी गंज रोड, प्रभाकर कालोनी,
जनपद–अयोध्या
मो0–7985197063

वाद सं0–28/2025 सेक्टर–2 श्री रवि साहू में पूर्व में 16.06.2025 की तिथि नियत थी आप उक्त नियत पर उपस्थित नही हुए और न ही प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में जबाब/स्वीकृत/शमन मानचित्र ही प्रस्तुत किया गया है।

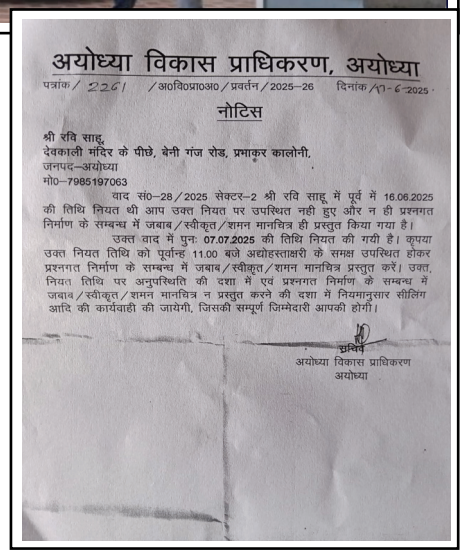

उक्त वाद में पुनः 07.07.2025 की तिथि नियत की गयी है। कृपया उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में जबाब/स्वीकृत/शमन मानचित्र प्रस्तुत करें। उक्त, नियत तिथि पर अनुपस्थिति की दशा में एवं प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में जबाब/स्वीकृत/शमन मानचित्र न प्रस्तुत करने की दशा में नियमानुसार सीलिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

...दन करने वाले का पदनाम	JE
प्रतिवेदन करने वाले की सिफ़ारिश	Uttar Pradesh City Planning and Development Act 1973 , 27 (1) ,28 (1) & 28 (2)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण अयोध्या-फ़ैज़ाबाद कार्यालय में दिनांक 16/06/2025 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

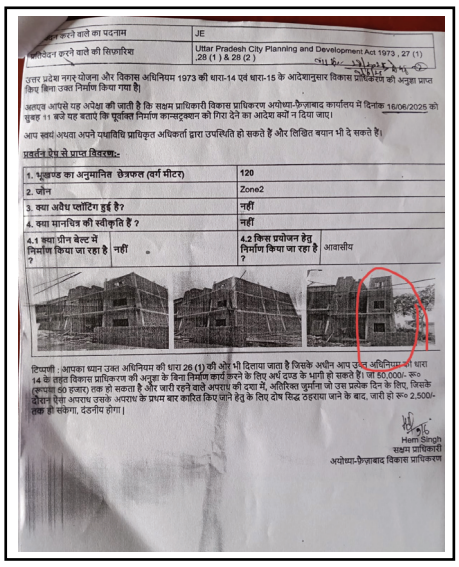

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

प्रवर्तन ऐप से प्राप्त विवरण:-

1. भूखण्ड का अनुमानित छेत्रफल (वर्ग मीटर)		120	
2. जोन		Zone2	
3. क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?		नहीं	
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति हैं ?		नहीं	
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं	4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय

टिप्पणी : आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्थ दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रू० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रू० 2,500/- तक हो संकेगा, दंडनीय होगा।

Hem Singh
सक्षम प्राधिकारी
अयोध्या-फ़ैज़ाबाद विकास प्राधिकरण

का अनुपालन ना होने के संदर्भ में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडेय का कहना है कि अभी सिर्फ सैद्धांतिक सहमति हुई है, शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

एडीए के जेई चंदन गुप्ता का कहना है कि हम साईट पर गए रवि को कागज दिखाने के लिए बुलाया गया वह 15 दिन तक नही आये तब नोटिस भेजी गई। 787 स्क्वायर फ़ीट की जगह 1200 स्क्वायर फ़ीट की नोटिस क्यों काटी गई इस सवाल पर उनका कहना है कि जब मालिक नही मिलता तो जो मौके पर मिलता है ठेकेदार मजदूर वह जो भी बताता है लगभग करके लिख दिया जाता है। इस मामले में किसी प्रकार की विभागीय चूक के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती नही हुई है।

संशय पर विराम : इस्राइल और ईरान युद्ध विराम पर हुए सहमत

» ट्रंप के एलान के बाद तेहरान ने इस्राइल पर अंतिम हमला किया

» इस्राइल ने भी सुबह से पहले ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। इस्राइल और ईरान ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में 12 दिनों से चल रहे युद्ध पर विराम लग गया। ट्रंप ने युद्ध विराम का एलान तेहरान की ओर से कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जवाबी सीमित मिसाइल हमलों के बाद किया था। इरान की यह कार्रवाई उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का जवाब थी।

ट्रंप के एलान के बाद बढ़े हमलों से मंडराया संकट : ट्रंप के एलान के बाद तेहरान ने इस्राइल को निशाना बनाकर मिसाइलों का अंतिम हमला किया, जिसमें मंगलवार सुबह कम से कम चार लोग मारे गए। जवाब में इस्राइल ने भी सुबह से पहले ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए।

सभी युद्ध लक्ष्य हासिल किए : प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल ट्रंप के साथ समन्वय में ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सोमवार रात को इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट को बताया कि इस्राइल ने ईरान के खिलाफ12 दिनों के अभियान में अपने सभी युद्ध लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, जिसमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खतरे को दूर करना भी शामिल है।

उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देने की बात कही

नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल ने ईरान के सैन्य नेतृत्व और कई सरकारी स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया और तेहरान के हवाई क्षेत्र पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। नेतन्याहू ने कहा, 'इस्राइल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देगा।'

इस्राइल-ईरान का सुबह-सुबह हमला

ट्रंप के सीजफायर के एलान के बाद सुबह 4 बजे से कुछ पहले तक ईरानी शहरों में भारी इस्राइली हमले जारी रहे, जिसके बाद ईरानी बमबारी ने इस्राइलियों को बंकरों में जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

ट्रंप ने दोनों देशों से की शांति की अपील

ईरान की ओर से अपने हमलों को रोकने के लिए समय सीमा बीत जाने के एक घंटे से अधिक समय बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'युद्ध विराम अब प्रभावी है। कृपया इसका उल्लंघन न करें!' ईरानी सरकारी टेलीविजन ने बताया कि युद्ध विराम सुबह 7:30 बजे प्रभावी हो गया।

पहले ईरान ने किया समझौते से इनकार

ट्रंप के एलान के बाद पहले ईरान ने किसी भी समझौते से इनकार किया और फिर कुछ घंटे बाद ही ईरान के शीर्ष राजनयिको की ओर से कहा जाने लगा कि देश हवाई हमलों को रोकने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने किया संघर्ष विराम का एलान

इस्राइल के सबसे बड़े शहर में सीधा हमला ट्रंप के युद्ध विराम लागू होने से पहले हुआ। ट्रंप ने कहा था कि इस्राइल-ईरान ने पूर्ण और समग्र युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप की घोषणा में कहा गया कि वॉशिंगटन समय के अनुसार आधी रात को शुरू होने वाला युद्ध विराम युद्ध का आधिकारिक अंत लाएगा।

जांच कमेटी गठित

अलीगढ़ के जीएसटी उपायुक्त अखिलेश कुमार सिंह निलंबित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/अलीगढ़। जीएसटी विभाग में बड़े प्रशासनिक एक्शन के तहत अलीगढ़ के उपायुक्त अखिलेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। शासन स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनके खिलाफ गंभीर अनियमितताओं और शासकीय कार्य में लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रकरण की जांच के लिए आईएएस अधिकारी धनंजय शुक्ला की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। यह समिति संबंधित दस्तावेजों और कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेगी। बताया जा रहा है कि उपायुक्त पर वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ विभागीय निदेशों की अवहेलना के आरोप हैं।

पूर्व मंत्री सड़क हादसे में घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। गोरखपुर के कैमपियरगंज से भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब वे एक निजी वाहन से यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन का अचानक संतुलन बिगड़ने से यह दुर्घटना हुई। हादसे में फतेह बहादुर सिंह को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

राहुल ने फिर उठाया चुनाव में धांधली का मसला

कोई मुद्दा है तो हम मिलने को तैयार : चुनाव आयोग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों पर राहुल गांधी से कहा कि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है, तो आप हमें लिख सकते हैं और हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार हैं। इस बीच राहुल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि मशीन की ओर से पढ़े जा सकने वाले डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी की जाए।

चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के उनके आरोपों पर औपचारिक रूप से पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी चुनाव संसद की ओर से पारित कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरे चुनाव अभ्यास में हजारों लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ-स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। चुनाव प्राधिकरण ने कहा, 'यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है, तो आप हमें लिख

सकते हैं।' वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि कुछ गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि वोटों की चोरी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 'एक्स' पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में नागपुर दक्षिण पश्चिम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की सीट पर 29,219 नए मतदाता जुड़े। महाराष्ट्र के सीएम के अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ पांच महीनों में मतदाता सूची में आठ फीसदी की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20-50 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

'प्लीज बचा लो...मुझसे कराते हैं गंदा काम'

बालिका के शरीर सिगरेट से दागने और चोट के निशान देख पुलिस हैरान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। आगरा के सदर क्षेत्र में नौ वर्षीय बालिका की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। बालिका ने महिला के चंगुल से भागकर एक राहगीर से मदद मांगी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। उसने विरोध करने पर पीटने, सिगरेट से दागने की बात की।

प्लीज मुझे बचा लो, मैं भागकर आई हूं, यह देखो मेरे शरीर पर चोटों के निशान, ये (गीता) मुझसे गलत काम (देह व्यापार) कराती है। छुट्टन, गीता का बेटा अमित तीनों मना करने पर मारते हैं, मैं छत से कूदकर, भागकर आई हूं। जब मासूम बालिका ने यह बात कही तो मददगार अजय सिंह के साथ पुलिस की भी रूह कांप गई।

बालिका ने बताया कि मैंने घर की कुंडी लगा दी थी। उसकी शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे। सिर और हाथों से खून भी निकल रहा था। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। डीसीपी सिटी सोनम कुमार के मुताबिक, बालिका ने पूछताछ में बताया है कि देह व्यापार के विरोध पर उसे पीटा जाता था। सिगरेट से दागते भी थे। गीता का बेटा पीटता था। घर का काम भी कराया जा रहा था। घर से बाहर निकलने की मनाही थी।

गीता के बड़े बेटे को बनाया आरोपी

गीता के बड़े बेटे अमित को भी आरोपी बनाया जा रहा है। वहीं उसका एक बेटा नाबालिग है। वह भी मारपीट करता था। उसे भी जांच के बाद आरोपी बनाया जाएगा। अजय सिंह की तहरीर पर देह व्यापार निवारण अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के तहत केस लिखा गया है। इसमें (कथित मां) गीता, मोहित, दिलीप कुमार, शोहिल को नामजद किया गया है।

नौ साल की बालिका को खरीदा... करा रहे थे देह व्यापार

आगरा के सदर क्षेत्र में नौ वर्षीय बालिका की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार कराने का मामला सामने आया है। मामला मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा होने के कारण एसीपी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। न्यू सीता नगर निवासी अजय सिंह भारतीय किसान यूनियन स्वराज के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम को किसी काम से ग्वालियर मार्ग पर गए थे। तभी एक बालिका उनके पास रोते हुए आई। हाथ जोड़कर पैरों में गिर गई। बालिका को पानी पिलाने के बाद पूछताछ की।

वह किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर सकती थी। उस पर आरोपी नजर रखते थे। गीता उसका मुंह बांधकर रखती थी, जिससे चीख न सके। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। कई जगह चोट और दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फिलहाल बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल गृह भेजा गया है। डीसीपी सिटी ने बताया कि बालिका के साथ ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।